gardens are being used for producing hybrids which are being tested for their resistance. The first set of planting shows encouraging results. Identifying resistant and tolerant lines is the long lasting solution.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों हेतु आवासीय स्कूल

*179. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-

जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने-कितने आवासीय स्कूल हैं;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे और स्कूल खोलने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या करण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्वीकृत किए गए आवासीय स्कूलों की कुल संख्या 377 है जिसमें से 111 आवासीय स्कूल अनुसूचित जाति छात्रों और 266 अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए हैं। योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना संलग्न विवरण 1 से 4 में दी गई है। (नीचे देखिए) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय स्कूलों की कोई योजना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए बड़ी संख्या में आवासीय स्कूल राज्य सरकारों तथा कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी चलाए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजनावधि की शेष अवधि में अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 58 और ऐसे आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों/स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य संगत उद्देश्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

"अनुसूचित जातियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता" की योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आवासीय स्कूलों का ब्यौरा

क्रम. सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासीय स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	बिहार	10
3.	गुजरात	01
4.	कर्नाटक	22
5.	मध्य प्रदेश	03
6.	मणिपुर	01
7.	उड़ीसा	06
8.	राजस्थान	03
9.	तमिलनाडु	02
10.	त्रिपुरा	02
11.	उत्तर प्रदेश	33
12.	पश्चिमी बंगाल	05
	कुल	111

विवरण-II

1990-91 से 1994-95 तक योजना के आरम्भ से आश्रम स्कूलों की स्थापना की योजना के अंतर्गत आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में स्थापित किए गए आश्रम स्कूलों की संख्या

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	20
2.	दमन और दीव	01
3.	गुजरात	45
4.	कर्नाटक	07
5.	केरल	10
6.	महाराष्ट्र	39
7.	उड़ीसा	20
8.	राजस्थान	02
9.	सिक्किम	03
10.	तमिलनाडु	24
11.	त्रिपुरा	08
12.	उत्तर प्रदेश	06
	कुल	185

विवरण-III

आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत किए गए शैक्षिक परिसरों की संख्या

क्र॰सं॰	राज्य	परिसरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	बिहार	01
3.	गुजरात	05
4.	केरल	01
5.	मध्य प्रदेश	14
6.	महाराष्ट्र	01
7.	उड़ीसा	15
8.	राजस्थान	11
	कुल	49

विवरण-IV

अनुसूचित जातियों के लिए स्वंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आवासीय स्कूलों का ब्यौरा

क्र॰सं॰	राज्य	स्कूलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	असम	02
4.	बिहार	06
5.	गुजरात	01
6.	कर्नाटक	02
7.	केरल	01
8.	मध्य प्रदेश	01
9.	मणिपुर	01
10.	मेघालय	01
11.	उड़ीसा	04
12.	राजस्थान	01
13.	उत्तर प्रदेश	04
14.	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	32

Setting up of Private Sector Steel Projects in Madhya Pradesh

*180. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Madhya Pradesh regarding issuance of letter of intent to private sector for setting up steel projects;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of Government thereon; and

(d) the names of the private sector undertakings recommended by the Madhya Pradesh Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Under the New Industrial Policy announced in July 1991, 'iron and steel' industry has been removed from the list of industries reserved for public sector and has also been exempted from the purview of compulsory licensing, except for certain locational restrictions, for which Govt. approval is required. The Union Government have not received any proposal from the Madhya Pradesh Government regarding issuance of letter of intent to private sector for setting up of steel projects.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

Comprehensive Watershed Development Project

1208. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned any comprehensive watershed development project with foreign assistance to the State of Maharashtra;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether some other externally aided projects in agricultural sector are being implemented in Maharashtra; and

(d) if so, the details thereof?